



Neutral Citation No-2026:AHC:8755

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी सं- 5345 वर्ष 2025

हरकेश सैनी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: सत्येंद्र पांडे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं- 54

माननीय न्यायमूर्ति श्री दिनेश पाठक

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. प्रस्तुत रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित राहत की मांग की गई है: -

"I. परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करता है, जिसमें चकबंदी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के चक संख्या-980 को न्यू गाटा संख्या-30 क्षेत्र 0.089 एच उत्तर प्रदेश सीएच नियम 1954 के नियम 109ए(1) के तहत 09-10 (हरकेश बनाम राज्य) के मामले संख्या-4 में परगना और तहसील-पर निपटान क्षेत्र के अनुसार मौके पर कब्जा देने का निर्देश दें, जैसा कि प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2009 में उल्लिखित है।

3. याचिकाकर्ता को प्लॉट संख्या-132 एम, 0.089 हेक्टेयर क्षेत्र का कब्जा दिया गया था, जो जनहित याचिका संख्या-43603 वर्ष 2007 में माननीय खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.08.2008 के आदेश के अनुसरण में, रिट याचिका संख्या-20886 वर्ष 2000 के परिणाम के अधीन था। इसके बाद, रिट बी संख्या-20886 वर्ष 2000 को दिनांक 25.03.2022 के आदेश



द्वारा वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया गया था। तब से, याचिकाकर्ता ने चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 07.10.2009 के आदेश के अनुसरण में प्लॉट संख्या-30 के कब्जे की डिलीवरी की मांग करते हुए संबंधित अधिकारियों को कई अभ्यावेदन दिए हैं। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया अभ्यावेदन अभी भी जिला चकबंदी उप निदेशक/कलेक्टर बुलंदशार के समक्ष विचारार्थ लंबित है।

4. स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि जनहित याचिका संख्या-43603 वर्ष 2007 में माननीय खंड पीठ द्वारा पारित दिनांक 01.08.2008 के आदेश के अनुसरण में, चकबंदी अधिकारी द्वारा पारित आदेश के कार्यान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 07.10.2009 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए जाने वाले नए अभ्यावेदन के शीघ्र निपटान के लिए निर्देश जारी किया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

5. इस परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस मामले को लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा; इसलिए, यह न्यायालय प्रस्तुत रिट याचिका में उल्लिखित मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, प्रस्तुत रिट याचिका को अंतिम रूप से निपटाने के लिए उचित समझता है, इस निर्देश के साथ कि याचिकाकर्ता अपनी शिकायत के संबंध में चकबंदी के जिला उप निदेशक/कलेक्टर (प्रतिपक्षी संख्या-2) के समक्ष एक नया अभ्यावेदन पेश करने के लिए स्वतंत्र है, जैसा कि प्रस्तुत याचिका में उल्लेख किया गया है, आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ तारीख के साथ-साथ आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर प्रस्तुत रिट याचिका की एक स्व-सत्यापित प्रति, जिस पर प्रतिपक्षी संख्या-2 द्वारा विचार और निर्णय लिया जाएगा, या तो स्वयं या सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से, जैसा कि कानून के तहत अनुमेय है, सख्ती से कानून के अनुसार, शीघ्रता से अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति के उत्पादन की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर।

6. उपरोक्त निर्देश के साथ, प्रस्तुत रिट याचिका का **निस्तारण** किया जाता है।

जनवरी 13, 2026

वीकेजी

(न्यायमूर्ति दिनेश पाठक)